

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 159
21 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

डेयरी सहकार योजना

159# श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) डेयरी सहकार योजना का क्या उद्देश्य है;
- (ख) क्या सरकार द्वारा इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए 5000 रुपये करोड़ के निवेश से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की स्थापना की गई है;
- (ग) क्या इस योजना के अंतर्गत पात्र समूह को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;
- (घ) क्या समूह के सदस्यों को डेयरी क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए देश में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं; और
- (ङ) यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ङ.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 159 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण, जिसका उत्तर 21 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

(क): डेयरी सहकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), जो भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निगम है, की एक सहकारी डेयरी व्यवसाय केंद्रित छत्र योजना है।

डेयरी सहकार का उद्देश्य ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) से जुड़ी गतिविधियों में उच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके "सहकार से समृद्धि तक" की दृष्टि को साकार करना है। इसमें नई तथा आधुनिक डेयरी का सृजन तथा/या वर्तमान दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद सुविधाओं का विस्तारण करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

डेयरी सहकार के तहत, एनसीडीसी द्वारा "किसानों की आय को दोगुना करने" और "आत्मनिर्भर भारत" के समग्र उद्देश्यों के भीतर पात्र सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख): एनसीडीसी की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक निगम के रूप में सहकारी समितियों के माध्यम से (i) कृषि उपज, खाद्य के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने, बढ़ावा देने और वित्तपोषण करने (ii) लघु वन उपज का संग्रह, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और निर्यात और (iii) अधिसूचित सेवाओं का विकास करने के लिए की गई थी।

डेयरी सहकार के तहत, एनसीडीसी भारत सरकार की प्रासंगिक योजनाओं के साथ जुड़कर डेयरी सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(ग): जी महोदय, डेयरी सहकार योजना के तहत डेयरी क्षेत्र की सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एनसीडीसी ने इस योजना के तहत सहकारी समितियों को 44.57 करोड़ रुपये (09.12.2022 तक) की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(घ) और (ड.): सहकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से सहकारी प्रशिक्षण का संचालन कर रहा है। एनसीसीटी के देश भर में 20 प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें 1 राष्ट्रीय स्तर संस्थान (वैमनिकॉम, पुणे), 5 क्षेत्रीय संस्थान और 14 राज्य स्तरीय संस्थान शामिल हैं। एनसीसीटी के तहत एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में भी स्थित है। एनसीसीटी सहकारी ऋण और गैर-ऋण क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है जिसमें डेयरी क्षेत्र भी शामिल है।

इसके अलावा, एनसीडीसी अपने लक्ष्मणराव इनामदार नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट (LINAC) के माध्यम से डेयरी सहित सभी सहकारी क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षित कर रहा है।
